

(तिथि 22 जुलाई 2026, समय 18:10 (10 मिनट))

मुख्य समाचार:

- संसदीय कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने कहा- सरकार ने विपक्षी दलों को नीट मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं।
- केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के खिलाफ बताया।
- चंडीगढ़ में चल रही 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के दूसरे दिन सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा और सशक्त स्वास्थ्य प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
- केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ सहकारिता नीति-2026 का शुभारंभ किया।
- सांसद नवीन जिन्दल ने कैथल में आरकेएसडी नवीन अवसर अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया।

संसदीय कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था।

देखिए जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहती है वो तो बोलना ही चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिन

से ऑफर किया है सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान टालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे, ताकि चर्चा ही न हो ये तो ठीक बात नहीं है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।

संवैधानिक पद पे रहके, संविधान की गरिमा को तार-तार किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहां उपद्रव कराना चाह रहे हैं।

भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष द्वारा किए गए प्रदर्शन को लोकतांत्रिक और कानून-व्यवस्था के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा स्थलों में से एक है। ऐसे स्थान तक पैदल मार्च कर धरना-प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है और यह कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। श्री गुर्जर ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों का समाधान खोजने के बजाय केवल व्यवधान उत्पन्न करने की राजनीति कर रहा है। विपक्ष भोले-भाले विद्यार्थियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

चंडीगढ़ में आयोजित चार दिवसीय 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक के दूसरे दिन सचिव स्तर की बैठक में सदस्य देशों ने डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा, महामारी की तैयारी और सशक्त स्वास्थ्य प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने आयुष पवेलियन, भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की खाद्य सुरक्षा वेब का दौरा किया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 'हेल्दी स्नेक्स एंड लैडर्स' गेम ने स्वस्थ खानपान का संदेश "जहां पौष्टिक भोजन आगे बढ़ाता है और अस्वास्थ्यकर भोजन पीछे ले जाता है" बड़े रोचक अंदाज़ में दिया।

बैठक के दौरान भारत ने आयुष की समृद्ध परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। आयुष ज़ोन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आयुष आहार, वेलनेस, योग, हर्बल विरासत और अनुसंधान-नवाचार से जुड़े विभिन्न आयामों का अनुभव करेंगे। इस पहल ने पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ सहकारिता नीति-2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जन सेवाओं में सुधार लाना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

इस नीति में सेवा सहकारी समितियों पर विशेष बल दिया गया है, जो विद्युत मरम्मत, प्लंबिंग, पेंटिंग, सफाई, सौर ऊर्जा स्थापना तथा छोटे-मोटे मरम्मत कार्य जैसे क्षेत्रों में कार्य करेंगी। ये समितियां आवासीय सोसायटियों एवं नागरिकों को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती सेवाएँ उपलब्ध कराएंगी, साथ ही कुशल श्रमिकों और आई टी आई से प्रशिक्षित युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक लगभग 50 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन एवं निगरानी हेतु चंडीगढ़ सहकारी विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा।

*

सांसद नवीन जिन्दल ने आज कैथल में आरकेएसडी कॉलेज परिसर में आरकेएसडी नवीन अवसर अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत कुरुक्षेत्र और कैथल के लिए करीब 520 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जिससे दोनों जिलों के युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि पीएम सेतु योजना के तहत मिलने वाली राशि से दोनों जिलों के आईटीआई संस्थानों को आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में नवीन जिन्दल ने कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस की शुभकामनाएं दीं।

आज अंबाला शहर की डेहा कॉलोनी में नगर निगम और पुलिस ने लगभग 12 मकानों को सील करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उन मकानों पर की गई, जिनके मालिकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

सिटी थाना प्रभारी सुनीता ढाका ने कार्रवाई के दौरान बताया कि नगर निगम दस्ते की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात किया गया है।

आज शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह के सहयोग से एक स्टॉल का शुभारंभ किया गया। वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट एवं अवसर योजना के अंतर्गत शुरू किए इस स्टॉल का उद्घाटन लुधियाना के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय के संयुक्त निदेशक पंकज कुमार झा तथा चंडीगढ़ के उद्योग विभाग कार्यालय के अधीक्षक विशाल सभरवाल ने किया।

इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध कराना है, जिससे पारंपरिक कारीगरों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी तथा चंडीगढ़ की समृद्ध स्थानीय हस्तशिल्प परंपरा को बढ़ावा मिलेगा।

इससे कारीगरों के लिए बाजार संपर्क मजबूत होंगे, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा तथा 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवा मुक्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए जिसमें जिला न्यायपालिका के जजों की सेवा मुक्ति की आयु 62 साल करने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके कोई फैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
